हम राजस्थानी • विकास की ओर बढ़ रहा प्रदेश

उद्योग 4.0 के लिए निवेश व स्थानीय प्रतिभा आवश्यक

इकोनॉमी

प्रदीप मेहता
सेक्रेटरी जनरल, कट्स इंटरनेशनल
psm@cuts.org

राजस्थान अगले पांच वर्षों में 350 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहा है। बीते पांच वर्षों में राज्य की जीडीपी में 8.8% की दर से वृद्धि दर्ज हुई। दूसरी ओर राज्य में निवेश की दर 8.5% रही है। लेकिन यह जीडीपी के अनुपात में संतोषजनक नहीं है। इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए, राज्य को अगले पांच वर्षों में 14.22% की वार्षिक वृद्धि की आवश्यकता है। मुद्रास्फीति की दर को यदि चार प्रतिशत मान लिया जाए तो राज्य को प्रगति के लिए लगभग 10% की वास्तविक वार्षिक विकास दर बनाए रखनी होगी। राजस्थान का आईसीओआर लगभग 1.88 है, जो महाराष्ट्र और तमिलनाडु जैसे राज्यों की तुलना में काफी कम है। आसान शब्दों में राज्य को निवेश को प्राथमिकता देनी होगी और अपनी पूंजी का कुशलतापूर्वक उपयोग करना होगा। इसके लिए निजी और सार्वजनिक दोनों निवेश को बढ़ाने के साथ रणनीतिक गठबंधनों, नीतिगत बदलावों और राइजिंग राजस्थान समिट जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों को प्रभावशाली बनाने पर ध्यान देना होगा।

इस प्रयास में पर्यटन और खाद्य प्रसंस्करण जैसे मजबूत सेक्टर्स के साथ सेमीकंडक्टर और ग्लोबल केपेबिलिटी सेंटर्स जैसे उभरते क्षेत्रों को प्राथमिकता देनी चाहिए। हालांकि नई पर्यटन नीति के माध्यम से निवेशकों को लुभाया जा रहा है। इसके अलावा राज्य में प्रस्तावित दो अरब डॉलर की भारत-यूएई खाद्य गलियारा परियोजना से भी अनेक उम्मीदें हैं। यह राज्य की आपूर्ति श्रृंखला को मजबूती देगा, निवेश को आकर्षित करेगा और रोजगार के नए अवसर पैदा करेगा। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और यूएई जैसे देशों के साथ साझेदारी स्थापित करने से राज्य को नए बिजनेस मॉडल और उन्नत प्रौद्योगिकियों को एकीकृत करने में मदद मिलेगी। उद्योग 4.0 के लिए IoT, AI, AR/VR, 3D प्रिंटिंग, ब्लॉकचेन और नवीकरणीय ऊर्जा जैसी तकनीकों का लाभ उठाना होगा। सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, डाटा आधारित प्रणालियों और ग्लोबल केपेबिलिटी सेंटर्स इस नए परिदृश्य में महत्वपूर्ण होंगे।

सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम और अंतरराष्ट्रीय साझेदारी जैसी पहलों से भारत वैश्विक सेमीकंडक्टर हब बनने की दिशा में प्रगति कर रहा है। सेमीकंडक्टर विनिर्माण और प्रतिभा विकास के लिए सरकार की 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर की प्रतिबद्धता इस यात्रा के केंद्र में है। राजस्थान भी सेमीकंडक्टर उद्योग में पहचान बना रहा है। भिवाड़ी में सहस्र सेमीकंडक्टर्स मेमोरी चिप्स का व्यावसायिक उत्पादन करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है। अधिक निवेश आकर्षित करने के लिए, 2021 में राज्य सरकार ने राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति शुरू की, जो इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन और विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन और बुनियादी ढांचे का समर्थन प्रदान करती है।

लेकिन प्रदेश को अपने प्रयासों में तेजी लाने की जरूरत है। खासकर सेमीकंडक्टर विनिर्माण का समर्थन करने के लिए एक कुशल कार्यबल विकसित करने की। आईटी और सॉफ्टवेयर विकास में स्थानीय प्रतिभा की कमी के कारण राजस्थान को जीसीसी को आकर्षित करने में चुनौतियों का

राजस्थान का आईसीओआर लगभग 1.88 है, जो महाराष्ट्र और तमिलनाडु जैसे राज्यों की तुलना में काफी कम है। आसान शब्दों में राज्य को निवेश को प्राथमिकता देनी होगी और अपनी पूंजी का कुशलतापूर्वक उपयोग करना होगा।

सामना करना पड़ रहा है। हालांकि आईआईटी जोधपुर, आईआईएम उदयपुर, एमएनआईटी जयपुर और बिट्स पिलानी जैसे संस्थानों के साथ कोचिंग हब कोटा का लाभ उठाते हुए प्रतिभा विकास पर ध्यान केंद्रित करके इस अंतर को घटाया जा सकता है।

2029 तक 350 अरब डॉलर के आर्थिक लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए राज्य एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा है। हमारी कल्पना है कि 2047 तक राजस्थान का कुल घरेलू सकल उत्पाद 500 अरब डॉलर तक पहुंचे। सभी राज्यों में उद्योग 4.0 के केंद्र में स्थित उद्योगों-अर्थव्यवस्था और वैश्विक क्षमता केंद्र (जीसीसी) में निवेश आकर्षित करने के लिए कड़ी प्रतिस्पर्धा के साथ राजस्थान को अपनी रफ्तार आगे बढ़ानी होगी। राज्य ने सराहनीय प्रगति की है, लेकिन लक्ष्य की प्राप्ति के लिए और आक्रामक होना पड़ेगा। प्रतिभा की कमी को पाटकर, व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देकर और उभरते उद्योगों पर पूंजी आकर्षित कर, राजस्थान नई औद्योगिक क्रांति में अग्रणी बन सकता है।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)